भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-211

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्थिति

†211. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वर्तमान स्थिति क्या है और स्थानीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने आस-पास के स्कूलों के विकास और शिक्षकों को पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए अपने सीएसआर कल्याणकारी योजनाओं के तहत सुधार प्रक्रिया को लागू करने के लिए क्या पहल की है;

(ख) क्या सरकार का मौजूदा 10+2 प्रारूप के स्थान पर 5+3+3+4 के नए शिक्षा प्रारूप के तहत अलग-अलग बोर्ड को मिलाकर एकल शिक्षा नीति बनाते हुए समस्त शिक्षा प्रणाली को एकीकृत करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देश में शिक्षा प्रणाली का सार्वभौमिक मॉडल लागू करने के लिए सरकार की नीति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की घोषणा दिनांक 29 जुलाई 2020 को की गई थी और इसने देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधारों का रास्ता बनाया है। एनईपी 2020 की घोषणा के बाद स्कूल शिक्षा में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। एनईपी 2020 की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक विस्तारित है। इसका उद्देश्य स्कूल की प्रभावशीलता को बेहतर बनाना है, जिसे स्कूल शिक्षा के लिए समान अवसर और निष्पक्ष अधिगम परिणाम के तौर पर मापा जाता है। इसकी संरचना को 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जो बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक चरण के अनुसार है। यह योजना शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के साथ पूरी तरह से अनुकूलित किया गया है।

- पीएम पोषण योजना: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना को नया रूप दिया गया है और सरकारी और सरकारी सहायता वाले स्कूलों में कक्षा I-VIII के विद्यार्थियों के अलावा बालवाटिका के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर, सभी स्कूलों में स्कूल पोषण गार्डन (एसएनजी) बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा समुदाय की भागीदारी को और सुदृढ़ करने के लिए, 'तिथि भोजन' नाम की एक विशेष पहल शुरू की गई है।

- आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ एफएस) दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को शुरु किया गया था। इसके आधार पर, कक्षा I और II के लिए अधिगम शिक्षण सामग्री (जादुई पिटारा) और पाठ्यपुस्तक जारी की गई हैं।

- स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ-एसई) दिनांक 23 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। एनसीएफ-एसई के तहत, पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ अनुकूलित किया गया है, जिसमें स्कूल शिक्षा के 5+3+3+4 डिज़ाइन पर बल दिया गया है। यह फ्रेमवर्क शुरुआती चरण से लेकर माध्यमिक चरण तक की पूरी शिक्षा यात्रा को संबोधित करता है। एनसीएफ-एसई (2023) के अनुसार कक्षा 3 से 8 के लिए पाठ्यपुस्तक जारी कर दी गई हैं।

- मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सार्वभौमिक बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसे बेहतर समझ और संख्याज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) कहा जाता है, दिनांक 05 जुलाई 2021 को शुरू किया गया।

- विद्या प्रवेश (वीपी), एक 3 माह का प्ले बेस्ड स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया और दिनांक 29 जुलाई, 2021 को शुरु किया गया था। यह मॉड्यूल 12 सप्ताह का है और इसमें कक्षा I में आने वाले बच्चों के विकास के अनुसार उपयुक्त निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चे की पूर्व-साक्षरता, पूर्व-संख्यात्मकता, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशलों को बेहतर

बनाया जा सके। विद्या प्रवेश अब एक वार्षिक कैलेंडर है और कक्षा I के 4.2 करोड़ से अधिक बच्चों को वीपी से लाभ हुआ है।

- एनसीटीई द्वारा दिनांक 22.10.2021 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए मानदंड और मानक अधिसूचित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक, 64 संस्थानों को 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए मान्यता दी गई, जिसमें 6,100 छात्र शामिल हुए।

- विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) दिनांक 06.09.2020 को शुरु किया गया।

- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) दिनांक 21 अगस्त 2019 को शुरू की गई और ईसीसीई के लिए मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण सहित स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों को कवर करने के लिए विस्तारित की गई।

- दिनांक 8 फरवरी, 2023 को परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना की गई ताकि छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक, दिशानिर्देश निर्धारित करने और गतिविधियों को लागू करने के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

- परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण दिनांक 4 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें सभी 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सरकारी स्कूलों (केंद्र और राज्य सरकार), सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों सहित स्कूलों के पूरे विस्तार को कवर किया गया था। देश भर में हुए इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य कक्षा 3, 6 और 9 के सैंपल छात्रों का मूल्यांकन करके स्कूल शिक्षा के बुनियादी, प्रारंभिक और माध्यमिक चरण तक पहुंचना था।

- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशागत मानक (एनपीएसटी) शिक्षकों के कार्य को बताते हैं और 21वीं सदी के स्कूलों में उच्च-गुणवत्ता, प्रभावशाली शिक्षण के तत्वों को स्पष्ट करते हैं, जिससे छात्रों के लिए शैक्षिक परिणाम बेहतर होंगे। एनसीटीई ने एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ बनाया है जो उन दक्षताओं को दर्शाता है जो शिक्षकों में अपनी भूमिकाएं प्रभावशाली तरीके से निभाने के लिए होनी चाहिए। एनपीएसटी मार्गदर्शक दस्तावेज़ दिनांक 9 मार्च 2024 को जारी किया गया था और अब यह 22 भारतीय अनुसूचित भाषाओं और ब्रेल संस्करण तथा श्रव्य प्रारुप में उपलब्ध है।

- नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग (एनएमएम) का उद्देश्य ऐसे बेहतरीन व्यावसायिकों का एक बड़ा समूह बनाना है जो स्कूल शिक्षकों को परामर्श देने के लिए तैयार हों। 'एनएमएम संबंधी ब्लूबुक' दिनांक 9 मार्च 2024 को जारी की गई थी और अब यह 22 भारतीय अनुसूचित भाषाओं और ब्रेल संस्करण और श्रव्य प्रारुप में उपलब्ध है।

- पीएम ई-विद्या के तहत, दीक्षा एक देश, एक डिजिटल शिक्षा अवसंरचना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा में शामिल किया गया है। यह डिजिटल अवसंरचना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस अवसंरचना का उपयोग एनर्जाइज्ड टेक्स्टबुक्स (ईटीबी) बनाने के लिए भी किया जा रहा है और अभी दीक्षा पर 7,497 ईटीबी प्रकाशित हो चुकी हैं। दीक्षा पर कुल 3,74,460 ई-कंटेंट और 135 भाषाओं (128 भारतीय+7 विदेशी भाषाएँ) में ई-कंटेंट उपलब्ध हैं।

- स्कूल शिक्षा के लिए स्वयम प्रभा के मौजूदा डीटीएच चैनल, जो उन लोगों तक पहुंचने और उनकी सहायता करने के लिए हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, को बढ़ाकर 200 चैनल कर दिया गया है, जिनमें कुल 92,147 वीडियो कंटेंट हैं, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /एबी से 30 भाषाओं में मिले 30585 घंटे के प्रसारण के बराबर हैं।

- पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 14500 से ज़्यादा चुने हुए स्कूलों को ऐसे स्कूलों के तौर पर विकसित करना है जो आस-पड़ोस के दूसरे स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करें और एनईपी 2020 की सभी पहलों को दर्शाएं।

- उल्लास (समाज में सभी के लिए जीवनपर्यंत अधिगम की समझ), प्रौढ़ शिक्षा पर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो एनईपी 2020 के साथ अनुकूलित है और इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के कम पढ़े-लिखे लोगों को शिक्षा के अवसर देना है। शिक्षार्थियों और स्वैच्छिक शिक्षकों को रजिस्टर करने और 26 भाषाओं में प्राइमर्स तक पहुंच देकर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिनांक 29.07.2023 को एक समर्पित मोबाइल ऐप शुरु किया गया था। 3.09 करोड़ से ज़्यादा शिक्षार्थियों और 46.52 लाख स्वैच्छिक शिक्षकों (वीटी) रजिस्टर हो चुके हैं। अब तक, 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात लद्दाख, गोवा, मिज़ोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से साक्षर घोषित किया जा चुका है।
- शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए अगले पाँच वर्षों में जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (डीआएईईटी) को धीरे-धीरे उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

देश भर के सरकारी स्कूल विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी (एनईपी) 2020 के अनुसार समुदाय और सीएसआर भागीदारी को आसान बनाता है। स्कूल स्वयं से अपनी विशेष आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हैं और पोर्टल पर सर्विसेज़ अथवा एसेट्स के लिए अपलोड करते हैं। ये अनुरोध पब्लिक डोमेन में सभी पंजीकृत योगदानकर्ताओं को सार्वजनिक रुप से दिखती हैं और स्कूल स्तर पर भागीदारी पूरी तरह से मांग पर आधारित रहता है।

विद्यांजलि एक स्कूल स्वैच्छिक प्रबंधन कार्यक्रम है जो देश भर में समुदाय और प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी के ज़रिए सरकारी और सरकारी सहायता वाले स्कूलों को सुदृढ़ बनाता है। दिनांक 07.09.2021 को इसकी शुरुआत से लेकर अब तक 8,33,082 से ज़्यादा सरकारी और सरकारी सहायता वाले स्कूल, 5,54,757 स्वैच्छिक और 2,365 सीएसआर/एनजीओ इसमें शामिल हो चुके हैं।

एनईपी 2020 में सभी स्कूल बोर्ड को एक राष्ट्रीय बोर्ड में मिलाने अथवा एक करने का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। तथापि, पॉलिसी में सभी बोर्ड में पहले के 10+2 फ़ॉर्मेट की जगह एक समान 5+3+3+4 संरचना की सलाह दी गई है, ताकि देश भर में विकास के लिए उपयुक्त और पाठ्यचर्या में एक जैसा तालमेल पक्का हो, और मौजूदा बोर्ड अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते रहें। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख को छात्र मूल्यांकन के लिए नियम और दिशानिर्देश तय करने और देश में स्कूल मूल्यांकन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय निकाय के तौर पर अधिसूचित किया है।

परख को देश भर के स्कूल बोर्ड द्वारा जारी किए गए कक्षा X और कक्षा XII के प्रमाणपत्रों के समतुल्यता प्रदान करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। परख की अगुवाई में 'बोर्ड्स की बराबरी' पहल का उद्देश्य शैक्षिक संभावनाओं में तालमेल बिठाना, अधिगम मानकों की तुलना को बेहतर बनाना और 60 से ज़्यादा स्कूल बोर्ड की विविधता तथा स्वायत्तता का सम्मान करते हुए बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना है।

******